

प्रेषक,

भास्करानन्द,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 14 मार्च, 2013

विषय:-श्री लक्ष्मी अम्माल ट्रस्ट, चेन्नई को ग्राम नगला एमाद, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (विश्वविद्यालय की स्थापना) हेतु कुल 10.00 एकड़ भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-144/जि0भू0व्यव0-2012 दिनांक-28.08.2012 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, श्री लक्ष्मी अम्माल एजुकेशन ट्रस्ट, चेन्नई को ग्राम नगला एमाद, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (विश्वविद्यालय की स्थापना) हेतु एक ही स्थान पर कुल 10.00 एकड़ भूमि कय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154(4)(3) (क)(III) के अन्तर्गत, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति एवं आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुति खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (विश्वविद्यालय की स्थापना) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का

उपयोग, जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 3- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 5- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7- संस्था द्वारा, प्रस्तावित भूमि का उपयोग, मात्र शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (विश्वविद्यालय की स्थापना) हेतु ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यो हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
- 8- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 9- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 10- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

- 11- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 12- उपरोक्त किसी भी शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जनपद स्तर से निर्गत आदेश की प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ०प०सं०- /समदिनांकित 2013

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- श्री लक्ष्मी अम्माल एजुकेशनल ट्रस्ट, 27/29 तिलक स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017
- 5- निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।